सत्ता का अहंकार घातक

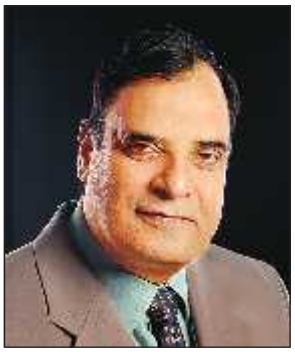

आलोक मेहता

जन लोकपाल कानून के लिए आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने पहले रंग बदलकर अरुणा राय का साथ छोड़ा। प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे, किरण बेदी और बाबा रामदेव के नाम और कंधों का इस्तेमाल कर केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच क्रांतिकारी मुखौटा लगाकर विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए 22 प्रतिशत वोट पाने में सफल हो गए। दिल्ली की लगभग 80 प्रतिशत जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस-भाजपा के राजनीतिक दांव-पेच के कारण केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। लेकिन अल्पमत के बावजूद वह दावा करते हैं कि दिल्ली की दो करोड़ जनता के सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकृत नेता हैं।

सत्ता की राजनीति का नया रूप। चुनाव की आंशिक सफलता का बड़ा अहंकार। भ्रष्टाचार, अपराध रोकने के नए फार्मूले। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ के बावजूद मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के अपने नियम-कानून और तालिबानी अंदाज में प्रमाण के बिना विदेशी महिलाओं के साथ घृणित दुर्व्यवहार तथा गैर कानूनी कार्रवाई। सत्ता का ऐसा दुरुपयोग आजादी के बाद देश के किसी हिस्से में देखने को नहीं मिला। आम आदमी के हितों के संरक्षण के नाम पर सत्ता की दहलीज पर पहुंचे अरविन्द केजरीवाल तथा उनके साथियों ने पिछले कुछ हफ्तों में राजधानी दिल्ली को दुनिया में बदनाम कर दिया। केजरीवाल के चहेते मंत्री सोमनाथ भारती 'जंगल-राज' की तरह रात को छापेमारी पर निकले तथा समुचित प्रमाण तथा वैधानिक चालान के बिना युगांडा-नाइजीरिया मूल की महिलाओं पर एक मोहल्ले की सड़क पर पुलिस कार्रवाई करवा दी। मादक पदार्थों के उपयोग तथा वेश्यावृत्ति के घृणित आरोप लगाकर उन्हें अपमानित कर दिया। आधी रात के बाद महिलाओं को जबरन पुलिस हिरासत में ले जाने का सोमनाथी फरमान ही गैर कानूनी था। मेडिकल जांच में भी महिलाओं पर लगे आरोप गलत साबित हुए। यही नहीं तुगलकी मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को समर्थकों की भीड़ के साथ अपमानित कर उन्हें ही दंडित कराने की मुहिम चला दी। मंत्री के अनुचित आदेश को नहीं मानने वाले पुलिसकर्मियों को शाबाशी देने के बजाय उनके निलंबन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल मंत्रिमंडल और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गये। आजादी के बाद देश के किसी मुख्यमंत्री ने इस ढंग से कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया। दो दिन की राजनीतिक नाटकबाजी के बाद वह पीछे हट गये, लेकिन आम आदमी और लोकतंत्र के नाम पर 'नई परंपरा' के खतरों की शुरुआत कर गये। केजरीवाल की पार्टी में तो नामी पिता-पुत्र वकील हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों और टी.वी. चैनलों के लिए जन सर्वेक्षणों से अपना 'साम्राज्य' बनाने वाले रणनीतिकार सलाहकार शीर्षस्थ नेता हैं। चुनाव अभियान के दौरान वोट के लिए झोली फैलाते समय इन नेताओं को यह नहीं मालूम हुआ कि मालवीय नगर खिड़की गांव इलाके में बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल के भोले-भाले युवा रहते हैं और समय-समय पर उन्हें अकारण पूर्वाग्रही यातना झेलनी पड़ती है। बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से आए गरीब लोगों तथा कहीं-कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ दिल्ली के कुछ मध्यमवर्गीय परिवार घटिया व्यवहार करते हैं। इसे उनकी नासमझी भी मानी जा सकती है। अपेक्षा यह थी कि मानव अधिकारों का ढोल पीटने वाले नेता ऐसे इलाकों में सामाजिक समरसता, परदेसियों के साथ सद्भाव के लिए अभियान चलाएंगे। लेकिन वे तो रंगभेदी टिप्पणी और भारत में किसी तरह जीवन-यापन कर रही महिलाओं को सबक सिखाने के वीभत्स अभियान में शामिल हो गये। प्रधानमंत्री पद और मेगसेसे के बाद नोबल पुरस्कार की आकांक्षा रखने वाले नेता वीभत्स घटना के बाद महिलाओं से क्षमा मांगने और अपने अपराधी साथी को न्याय के सुपुर्द करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए?

सूचना के अधिकार के लिए समर्पित ईमानदार समाजसेवी अरुणा राय का सहारा लेकर सार्वजनिक जीवन में घुसने वाले केजरीवाल ने पिछले वर्षों के दौरान अपने संरक्षकों और समर्थकों के साथ चालाकी से हर कदम पर धोखेबाजी की है। जन लोकपाल कानून के लिए आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने पहले रंग बदलकर अरुणा राय का साथ छोड़ा। प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे, किरण बेदी और बाबा रामदेव के नाम और कंधों का इस्तेमाल कर केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच क्रांतिकारी मुखौटा लगाकर विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए 22 प्रतिशत वोट पाने में सफल हो गए। दिल्ली की लगभग 80 प्रतिशत जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस-भाजपा के राजनीतिक दांव-पेच के कारण केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। लेकिन अल्पमत के बावजूद वह दावा करते हैं कि दिल्ली की दो करोड़ जनता के सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकृत नेता हैं।

गरीब जनता को मुफ्त पानी, सस्ती बिजली, छत, शिक्षा, इलाज की व्यवस्था को चुनावी वायदों पर आंखमिचौली का खेल करने के साथ वह हर नागरिक को स्वयं स्टिंग आपरेशन करने, भीड़ इकट्ठी कर प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई, केंद्र की सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और संपूर्ण व्यवस्था को भ्रष्ट बताने का अभियान चलाए हुए हैं। वह नब्बे प्रतिशत नेताओं, पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भ्रष्ट और निकम्मा ठहरा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में कैंसर की तरह फैला है। लेकिन किसी पुरानी घातक बीमारी को क्या रातोरात ठीक किया जा सकता है? वह प्रमाण के बिना ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ लोगों को भ्रष्ट तथा अपराधी कैसे बता सकते हैं? व्यवस्था की गड़बड़ियों से ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी सर्वाधिक दुखी होते हैं। केजरीवाल तो इनकम टैक्स की नौकरी से छुट्टी लेकर विदेश में एक बरस शिक्षा-दीक्षा पाए हैं और मैगसेसे पुरस्कार भी परदेस से लाए हैं। केजरीवाल की मंडली जिन संस्थाओं को चलाती रही, उन्हें फोर्ड फाउंडेशन जैसे विदेशी संस्थाओं से दान तथा कुछ संदिग्ध विदेशियों से 'कुशासन का ज्ञान' मिला हुआ है। तब भी क्या उन्हें नहीं पता कि बेहद सक्षम होते हुए वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिंगापुर, टोक्यो जैसी राजधानियों में भी बलात्कार, लूटपाट, हत्या की घटनाएं होती हैं। अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण का शर्तिया फार्मूला कोई नहीं बता सकता है। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार के लिए अच्छी शिक्षा के साथ सामाजिक जागरुकता के अभियान की जरूरत होती है। प्रशासन तंत्र में सुधार भी रातोरात नहीं हो सकता। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में बड़ी क्रांतियां और सत्ता परिवर्तनों के बाद आए सत्ताधारी क्या समाज को पूरी तरह राहत दिला सके? सैनिक तानाशाह आने पर भी क्या भ्रष्टाचार रुक पाया? केजरीवाल की सरकार और पार्टी पांच सालों में धीरे-धीरे सही कदम उठाकर कुछ समस्याओं का समाधान कर सकती है। लेकिन तालिबानी नियम-कानून लागू कर सब कुछ बदल देने की कोशिश समाज के लिए अभिशाप बन जाएगी। कल्पना कीजिए जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नगालैण्ड में केजरीवाल फार्मूले पर सत्ता की मनमानी, जनमत संग्रह होने लगे, तो देश के लिए कितने खतरे बढ़ जाएंगे? अफ्रीकी या खाड़ी के देशों में भारतीय मूल के लोगों पर भी झूठे आरापों के आधार पर पुलिस कार्रवाई होने लगी, तो कितना भयावह होगा? इसलिए 'आप' को समय रहते सोचना और संभलना होगा, क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती।

alokmehta7@hotmail.com